(क) मध्य प्रदेश में 30-6-93 तक कुल कितनी लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं और उनकी कुल सिंचन क्षमता कितनी है ;

(ख) पूर्ण निर्मित लघु सिंचाई योजनाओं की तथाकथित एवं वास्तविक सिंचन क्षमता कितनी है और इनके बीच अन्तर होने के क्या कारण हैं ;

(ग) प्रदेश में कितनी ऐसी निर्मित लघु सिंचाई योजनाएं हैं जिनकी सिंचन क्षमता तथाकथित सिंचन क्षमता की तुलनाओं में मात्र शून्य से 25 प्रतिशत ही है और उसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(घ) निर्माणाधीन योजनाओं में से कितनी योजनाओं में 50% से भी कम क्षेत्रों में तथाकथित क्षमता से कम सिंचन होने की संभावना है ; और

(ङ) इन निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं में, जिनमें तथाकथित सिंचन क्षमता से 50% एवं 25% से भी कम सिंचन क्षमता है या होने की संभावना है, उनके निर्माण पर प्रथम प्राक्कलित लागत राशि एवं वास्तविक लागत राशि का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ङ) लघु सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता है । इन स्कीमों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है ।

Telugu-Ganga Project

2410. SH. BISHAMBHAR NATH PANDE : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that efforts have been made to meet the Water Scarcity of Madras city through expeditious implementation of Telugu-Ganga Project;

(b) if so, what are the details of the project implementation till date; and

(c) whether it is also a fact that the project implementation has been delayed because of escalation of the cost ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Telugu-Ganga Project envisages to deliver 15 Thousand Million Cubic Feet (TMC) of Krishna waters at Andhra Pradesh-Tamil Nadu Border to meet drinking water requirements of Madras city in addition to utilisation of 29 TMC of Krishna waters and 20.2 TMC of Pennar waters for enroute irrigation in Rayalaseema region of Andhra Pradesh. The project has been techno-economically examined but its consideration was deferred by the Advisory Committee due to non-resolution of inter-State issues concerning utilisation of 29 TMC of Krishna waters for irrigation. The Chief Ministers of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have taken upon themselves the resolution of inter-States issue in the project. Already the project has been accorded environmental and forest clearances in 1988. The project has been included in the VIII Plan proposals of Andhra Pradesh. Against the latest estimated cost of Rs. 1254 crores, an amount of Rs. 542.46 crores has been spent till the end of June, 1993. While the State Government has programmed to complete the project by 1999-2000, Tamil Nadu is scheduled to receive water releases for Madras city by 1995.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

2411. **श्री विनीत सिंह पटेरिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान "उद्वहन और स्टापडेम" योजनाओं के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और इन योजनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितने क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया गया है ;

(ख) इन योजनाओं के द्वारा सृजित की गई कुल सिंचाई क्षमता में से कुल कितने क्षेत्र में वास्तविक रूप से सिंचाई की जा रही है ;

(ग) क्या राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में, इन योजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई की संभावनाओं की वास्तविक उपयोगिता और इस पर व्यय होने वाली राशि के संबंध में पहले कभी कोई आकलन किया गया है ; और

(घ) राज्य के बस्तरांचल क्षेत्र में उन इलाकों का जिलेवार ब्यौरा क्या है, जिनमें इन योजनाओं द्वारा सृजित कुल सिंचाई की संभावनाओं में से सिंचाई सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है तथा इन योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) उद्वहन और स्टापडेम स्कीमें सामान्यतया लघु सिंचाई स्कीमें हैं जो स्वयं राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं । उनका ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है । राज्य सरकार के योजना दस्तावेज में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई स्कीमों पर 125.23 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गयी